एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (असर 2014) जारी
नई दिल्ली, 13 जनवरी 2015

एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट, असर 2014 आज नई दिल्ली में जारी हो गयी. यह दसवीं वार्षिक रिपोर्ट है.

असर ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा और बुनियादी शिक्षण पर केन्द्रित बच्चों का सबसे बड़ा परिवार आधारित वार्षिक सर्वेक्षण है. प्रथम द्वारा प्रायोजित और प्रत्येक ग्रामीण जिले में होने वाला यह सर्वे वस्तुतः स्थानीय संगठनों व संस्थाओं द्वारा संपन्न किया जाता है. असर 2014 की पहुंच 577 जिलों और 16,497 गांवों तक रही तथा इसमें करीब 340,000 परिवारों के 3-6 आयुवर्ग के 570,000 बच्चों के बारे में जानकारियां जुटाई गईं.

हर वर्ष, असर यह पता लगाने का प्रयास करता है कि ग्रामीण भारत में क्या बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, क्या वे एक सरल पाठ को पढ़ पाने और बुनियादी गणितीय क्रियाओं को कर पाने में सक्षम हो पाए हैं. वर्ष 2005, 2007 में और 2009 के बाद हर वर्ष असर में सर्वेक्षित गांवों के एक-एक सरकारी स्कूल को भी सर्वेक्षण के दायरे में रखा गया है. वर्ष 2010 में आरटीई क़ानून के लागू होने का बाद असर के स्कूल सर्वेक्षण में उन मापे जा सकने योग्य मानकों की पड़ताल को भी शामिल किया गया, जिन्हें इस कानून के तहत अपरिहार्य कर दिया गया है. 2014 के असर में 15,206 सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया.

असर 2014 रिपोर्ट के लोकार्पण समारोह में असर के देश विदेश के प्रमुख सहयोगी संगठनों ने भी हिस्सेदारी की. इस मौके पर एकाउन्टेबिलीटी इनिशिएटिव की निदेशक यमिनी अय्यर ने कहा कि सरलता असर की सबसे बड़े ताकत है और असर की वजह से उनकी संस्था और उनका काम खड़ा हो पाया. उन्होंने बताया कि किस तरह असर ने नागरिकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया है.

इस मौके पर असर पाकिस्तान की संस्थापक बेला रजा ज़मील और पूर्वी अफ्रीका में असर संचालक सारा रुटो ने बताया की किस तरह उन्होंने असर से प्रेरणा लेकर अपने-अपने देशों में यही कार्यक्रम शुरू किया. उन्होंने बताया की आज असर उनके देशों में शिक्षा सुधार का असरदार औजार बन गया है.

रिपोर्ट को जारी करते हुए प्रथम के बोर्ड चेयरमान अजय पिरामल ने असर की दस साल की यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए याद दिलाया की शुरू में लोगों ने असर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किये थे और आज इसका तमाम सरकारी और गैर सरकारी नीति नियोजनों में उल्लेख किया जाता है.

समारोह में ह्युलेट फाउंडेशन की रूथ लेवाइन और प्रथम यूएसए के अध्यक्ष दिन्यार देवित्रे, प्रथम के अध्यक्ष माधव चौह्वान, असर की निदेशक रुक्मिणी बनर्जी ने भी संबोधित किया.

इस मौके पर मोबाइल के लिए असर का अप्लिकेशन भी जारी किया गया. असर के आंकड़ों को मोबाइल में हासिल करने की सुविधा देने वाले वाले इस एप को रोहिणी निलेकणी ने जारी किया.

असर 2014: प्रमुख निष्कर्ष

वर्ष 2014 लगातार छठा वर्ष है, जब स्कूलों में 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन की दर 96% या उससे ज्यादा रही है. स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 3.3% रहा.

- भारत 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के सार्विक नामांकन के लक्ष्य के नज़दीक है. पिछले छः वर्षों से इस आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन की दर 96% या इससे अधिक रही है.
- राष्ट्रीय स्तर पर, स्कूल नहीं जाने वाले 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का प्रतिशत 3.3% बना हुआ है. पिछले वर्ष भी यह इतना ही था.
- कुछ राज्यों में स्कूल नहीं जाने वाली (6-14 वर्ष आयुवर्ग की) लड़कियों का प्रतिशत 8% या उससे ज्यादा बना हुआ है. ये राज्य है- राजस्थान (12.1%) और उत्तर प्रदेश (9.2%).
- हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत आने वाले बच्चों (6-14 वर्ष आयुवर्ग) के नामांकन की दर बहुत ऊंची है, 15 से 16 वर्ष के अनामांकित बच्चों की संख्या अच्छी-खासी है. राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस आयुवर्ग के 15.9% लड़के और 17.3% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं.

प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ा है.

- वर्ष 2014 में, ग्रामीण क्षेत्रों के 6-14 वर्ष आयुवर्ग के 30.8% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं. यह संख्या 2013 (29%) से थोड़ी सी ही ज्यादा है.
- पिछले वर्षों की तरह, प्रत्येक आयुवर्ग में, प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले लड़कों सी संख्या लड़कियों की तुलना में ज्यादा रही. 2014 में 7-14 वर्ष आयुवर्ग के 35.6% लड़कों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों में हैं, जबकि लड़कियों में यह प्रतिशत 27.7% है. 11-14 वर्ष आयुवर्ग में 25.9% लड़कियों के मुकाबले 33.5% लड़के प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं.
- वर्ष 2013 की तुलना में लगभग सभी राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन की दर में वृद्धि दिखाई देती है. मात्र गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, नागालेंड और केरल इसके अपवाद हैं.
- भारत के पांच राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले प्रथामिक स्तर के बच्चों की संख्या 50% से ज्यादा हो गयी है. ये राज्य हैं- मणिपुर (73.3%), केरल (62.2%), हरियाणा (52.2%), उत्तर प्रदेश (51.7%) और मेघालय (51.7%).

पढ़ने की क्षमता का स्तर (रीडिंग लेवल) अब भी निम्न और अपरिवर्तनीय है.

- कुल मिला कर, भारत में पढ़ने की बुनियादी क्षमता की स्थिति अब भी बेहद निराशाजनक बनी हुई है. वर्ष 2014 में कक्षा 3 में लगभग एक चौथाई बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर के पाठ को धाराप्रवाह पढ़ पाने में सक्षम हैं. कक्षा 5 तक आते-आते यह संख्या सिर्फ आधे तक बढ़ पाती है. यहां तक कि कक्षा 8 में भी, लगभग 75% बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं. मतलब कक्षा 8 के 25% प्रतिशत बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं!
- पिछले कुछ वर्षों में पढ़ने की क्षमता में बहुत मामूली सुधार ही दिखाई देता है. उदाहरण के लिए, कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ लेने वाले कक्षा 5 के बच्चों की संख्या 2012 में 46.8% से 2013 में 47% और 2014 में 48.1% तक ही बढ़ पाई है. वर्ष 2012 में कक्षा 3 के 38.7% बच्चे कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ पाने में सक्षम थे. वर्ष 2014 में यह संख्या बहुत थोड़ी बढ़कर मात्र 40.2% तक पहुंच पाई.
- कुछ राज्यों में पढ़ पाने की क्षमता में पिछले साल की तुलना में सुधार दिखाई देता है. उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में पिछले वर्ष के मुकाबले कक्षा 5 के ऐसे बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ आसानी से पढ़ लेते हैं. तमिलनाडु ने पिछले वर्ष की तुलना में इस लिहाज़ से अच्छी प्रगति की है.
- समय के साथ रुझानों को देखें तो कई राज्यों में बच्चों की पढ़ने की क्षमता का स्तर यथावत बना हुआ है. फिर भी, कुछ राज्यों में, जैसे- बिहार, असम, झारखण्ड, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछले 5-6 वर्षों के दौरान पढ़ पाने में सक्षम बच्चों की संख्या में स्पष्ट गिरावट दिखाई देती है.

गणित अब भी चिंता का गंभीर और प्रमुख कारण बना हुआ है.

- प्रारंभिक गणित सम्बंधी अखिल भारतीय (ग्रामीण) आंकड़े पिछले कुछ वर्षों से लगभग अपरिवर्तनीय बने हुए हैं. वर्ष 2012 में कक्षा 3 के 26.3% बच्चे दो अंकों का घटा कर पा रहे थे. वर्ष 2014 में यह संख्या 25.3% है. कक्षा 5 के बच्चों में, भाग के सवाल कर पाने वाले बच्चों की संख्या 2012 में 24.8% से थोड़ा बढ़कर 2014 में 26.1% हो गयी है.
- अन्य रुझान अब भी चिंता का कारण बने हुए हैं. उदाहरण के लिए, कक्षा 2 के ऐसे बच्चों का प्रतिशत, जो 9 तक के संख्याओं को अब भी नहीं पहचानता, समय के साथ बढ़ा है. 2009 में यह आंकड़ा 11.3% था जो 2014 में बढ़कर 19.5% हो गया.

- इसी तरह, भाग के सवाल कर पाने में सक्षम कक्षा 8 के बच्चों की संख्या वर्ष 2010 से लगातार घट रही है. तीन अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या का भाग दे पाने में सक्षम कक्षा 8 के बच्चों की संख्या वर्ष 2010 में 68.3% थी. यह संख्या वर्ष 2014 में घटकर 44.1% रह गई.

- पिछले वर्ष की तुलना में बहुत थोड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं (तमिलनाडु को छोड़कर जहां सुधार दिखाई देता है). तथापि, पांच से आठ वर्ष के अंतराल पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग हर राज्य में गणित के स्तर में गिरावट आई है. कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश इसके अपवाद हैं, जहां पिछले कई वर्षों से स्थिति जस कि तस बनी हुई है.

निचली प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेज़ी पढ़ पाने की क्षमता की स्थिति यथावत बनी हुई है.

प्रारंभिक अग्रेज़ी सम्बंधी मूल्यांकन 2007, 2009, 2012 और 2014 में किया गया.

- निचली प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की अंग्रेज़ी पढ़ पाने की क्षमता तुलनात्मक रूप से जस की तस बनी बनी हुई है. वर्ष 2014 में कक्षा 5 में नामांकित लगभग 25% बच्चे ही अंग्रेज़ी के सरल वाक्यों को पढ़ पाते हैं. यह आंकड़ा वर्ष 2009 से अब तक लगभग यथावत है.
- मगर, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इस मामले में गिरावट दिखाई देती है. वर्ष 2009 में, कक्षा 8 के 60.2% बच्चे सरल वाक्यों को पढ़ पाते थे. लेकिन 2014 में यह आंकड़ा गिरकर 46.8% पर आ गया है.
- वर्ष 2014 में, किसी भी कक्षा के शब्द पढ़ लेने वाले बच्चों में मोटे तौर पर 60% इन शब्दों का अर्थ बता पाने में सक्षम हैं. पूरा वाक्य पढ़ लेने वाले कक्षा 5 के बच्चों में 62.2% उस वाक्य का अर्थ बता पाते हैं. कक्षा के हिसाब से देखें तो अर्थ (शब्द या वाक्य का) बता पाने वाले बच्चों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दिखाई देता है.

स्कूल के हाल

असर 2014 में प्राइमरी सेक्शन वाले 15,206 सरकारी स्कूलों का दौरा किया गया. इनमें 8,844 प्राइमरी और 6,362 ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें प्राइमरी कक्षाएं भी लगती हैं.

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शिक्षकों व बच्चों की उपस्थिति की स्थिति में ख़ास बदलाव नहीं दिखाई देता.

- वर्ष 2014 में असर के आंकड़े बताते हैं कि प्राइमरी स्कूलों के कुल नामांकित बच्चों में 71.4% और अपर प्राइमरी स्कूलों में 71.1% बच्चे सर्वेक्षण के दिन उपस्थित थे. वर्ष 2013 में ये आंकड़े क्रमशः 70.7% और 71.8% थे.
- पिछले वर्ष की तरह बच्चों की उपस्थिति की स्थिति पूरे देश में एक जैसी नहीं है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपस्थिति की दर 80 से 90% है. लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उपस्थिति दर काफी कम (50 से 60%) है.
- समय के साथ रुझान बताते हैं कि वर्ष 2009 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल दोनों में बच्चों की उपस्थिति की स्थिति 2014 के मुकाबले बेहतर थी. वर्ष 2009 में प्राइमरी स्कूलों में उपस्थिति 74.3% और अपर प्राइमरी स्कूलों में 77% थी.
- वर्ष 2009 से शिक्षकों की उपस्थिति में मामूली गिरावट दिखाई दे रही है. वर्ष 2014 में प्राइमरी स्कूलों में सर्वेक्षण के दिन 85% शिक्षक स्कूल में उपस्थित थे. वर्ष 2009 में यह आंकड़ा 89.1% था. अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए वर्ष 2014 शिक्षक उपस्थिति दर 85.8% रही जबकि वर्ष 2009 में यह 88.6% थी.

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में "छोटे स्कूलों" की तादाद लगातार बढ़ रही है.

- वर्ष 2014 में सर्वेक्षित सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एक तिहाई से ज्यादा "छोटे स्कूल" की श्रेणी में गिने जा सकते हैं, जहां कुल नामांकन संख्या 60 या इससे कम है.
- वर्ष 2009 में सर्वेक्षित सरकारी प्राइमरी स्कूलों "छोटे" स्कूलों की संख्या 26.1% थी.

अधिकांश हिस्सों में स्कूल सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है.

- आरटीई निर्देशित छात्र-शिक्षक अनुपात का पालन करने वालों स्कूलों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. पिछले वर्ष के 45.3% की तुलना में वर्ष 2014 में यह बढ़कर 49.3% हो गया है. वर्ष 2010, यह आंकड़ा 38.9% था.
- कार्यालय/गोदाम, खेल का मैदान, चारदीवारी और रसोईघर के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर साल दर साल प्रगति दिखाई देती है.
- पेयजल के प्रावधान और उपलब्धता के सन्दर्भ में सर्वेक्षित 75.6% स्कूलों में पेयजल उपलब्ध था. वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 72.7% था. चार राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश) में 85% से ज्यादा स्कूलों में पेयजल उपलब्ध था.
- असर ने यह देखने की भी कोशिश की कि क्या स्कूल दौरे के दिन स्कूल में इस्तेमाल लायक शौचालय था या नहीं. वर्ष 2010 से इस्तेमाल लायक शौचालयों की संख्या में लगातार सुधार

दिखाई देता है. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वर्ष 2014 में 65.2% स्कूलों में इस्तेमाल लायक शौचालय पाए गए. वर्ष 2013 में यह आंकड़ा 62.6% और वर्ष 2010 में 47.2% था. लड़कियों के लिए इस्तेमाल लायक शौचालय की मौजूदगी वर्ष 2010 में 32.9% थी, जो वर्ष 2013 में

- बढ़कर 53.3% और वर्ष 2014 में 55.7% हो गयी. चार राज्यों में 75% से ज्यादा स्कूलों में इस्तेमाल लायक बालिका शौचालय पाए गए. ये राज्य हैं- गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा.
- सर्वेक्षित स्कूलों में कम्पूटर की उपलब्धता की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई देता है. वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 19.6% है जो वर्ष 2010 में 15.8% था. इस मामले में कई राज्य बहुत आगे हैं. गुजरात में 81.3% सर्वेक्षित स्कूलों में कम्पूटर हैं. केरल में यह संख्या 89.8%, महाराष्ट्र में 46.3% और तमिलनाडु में 62.4% है.
- इसी तरह पुस्तकालय वाले स्कूलों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा सकती है. वर्ष 2010 में यह संख्या 62.6% थी जो वर्ष 2014 में बढ़कर 78.1% हो गई है. कुल सर्वेक्षित स्कूलों में से 40.7% में बच्चे पुस्तकालय का उपयोग करते पाए गए. वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 37.9% था.

असर की 10वीं सालगिरह के मद्देनज़र डेढ़ दिन के इस कार्यक्रम में कई दिलचस्प पैनल डिसकशन निर्धारित हैं. इन कार्यक्रमों में भारत भर से ऐसे लगभग 100 जिला स्तरीय संगठन और संस्थाएं हिस्सेदारी करेंगे, जो पिछले एक साल से असर के सहयोगी रहे हैं. इनके अलावा इस अवसर पर हमारे विदेशी सहयोगी भी हिस्सा ले रहे हैं. असर के मॉडल से प्रेरणा लेकर आठ अन्य देशों ने भी इसी तरह की पहल शुरू की है. पाकिस्तान, युगांडा, तंजानिया, माली, सेनेगल, नाइजीरिया और मेक्सिको से इन प्रयासों के अगुआ सदस्य 14 जनवरी की सुबह अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगे.